

प्रेषक,

डी0एस0 गबर्वाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 12 अक्टूबर, 2015

विषय : नव गठित नगर पंचायतों को कार्यालय स्थापना एवं कार्यालय व्यय हेतु अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में गठित नवीन नगर निकायों यथा- रानीखेत-चिलयानौला (जिला-अल्मोड़ा), नानकमत्ता (जिला-ऊधमसिंह नगर), गूलरभोज (जिला-ऊधमसिंह नगर), गजा (जिला टिहरी गढ़वाल) एवं भिकियासैण (जिला-अल्मोड़ा) को कार्यालय स्थापना के लिए नितान्त आवश्यक एवं Most Economical उपकरण/वस्तुओं के क्रय हेतु प्रति नगर निकाय ₹4.50 लाख की दर से, इस प्रकार उपरोक्त 05 नगर निकायों हेतु कुल ₹4.50 X 05 = ₹22.50 लाख (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि कुल ₹22.50 लाख (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रत्येक नवगठित नगर निकाय हेतु निर्धारित धनराशि ₹4.50 लाख सम्बन्धित नगर निकाय के प्रभारी अधिशासी अधिकारियों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष नगर निकायों द्वारा व्यय विवरण शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
4. उक्त धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
5. केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने का प्रयास वित्त आयोग निदेशालय से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।
6. नियमित व पर्याप्त आय प्राप्त करने हेतु नवगठित नगर पंचायतें त्वरित आधार पर कार्यवाही करेंगे।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

u

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28-03-2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-S.I.S./e/30/115.....के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

सं०-1319(1)/IV(2)-श०वि०-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एवं महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
9. प्रभारी अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
उप सचिव।